श्री सभापतिः प्लीज़। यह क्या हो रहा है? आपको बैठकर बोलना है और बार-बार बोलना है? हर एक क्वेश्चन के बारे में व्याख्या करते जाना, इस तरह से हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे? प्लीज़।

श्री हुसैन दलवईः मैंने पुलिस से complaint की और मुझे मालूम पड़ा और पुलिस ने ही मुझे बताया कि जो नाइजीरियन लोग थे, उनमें से तीन लोग पकड़े भी गए हैं, लेकिन उसके पीछे मुझे बहुत लगना पड़ा। मुझे एक एनजीओ ने यह कहा कि आप एमपी हैं, इसलिए ये लोग पकड़े गए, otherwise इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता है।

श्री सभापतिः आपका सवाल पूछिए।

श्री हुसैन दलवईः सर, पुलिस ने मुझे यह बताया कि जितने well equipped नाइजीरियन लोग hack करने वाले हैं, उतनी हमारी पुलिस यंत्रणा सजग नहीं है। आप मुझे बताइए कि सरकार पुलिस को इसके बारे में educate करने के लिए क्या करेगी?

श्री रवि शंकर प्रसादः सर, बार-बार सिक्योरिटी ड्रिल रखते हैं, ताकि ये चीफ सिक्योरिटी आफिसर्स हर एजेंसी में आएं। उनके लिए हम ट्रेनिंग प्रोग्राम रखते हैं। हम लोगों ने Botnet स्वच्छता केंद्र बनाए हैं और बाकी की भी सारी कार्रवाई करते हैं। अब स्पेशल आपके केस का जो मामला है, यदि आप मुझे बताएंगे, तो मैं तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करूंगा, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि मैं इसकी मॉनिटरिंग करता हूं। देश भर में आज पुलिस का साइबर सेल अपनी अनिश्चितताओं के बावजूद बहुत सक्रिय हो गया है और ट्रेनिंग बढ़ रही है, इसमें और काम करने की जरूरत है, मैं कोशिश करता हूं कि judges की भी ट्रेनिंग हो कि उनके पास ऐसे केसेज़ आएं, तो वे उनको किस प्रकार से डिसपोज़ ऑफ करें।

धान की खरीद

*250. **श्रीमती छाया वर्माः** क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) इस वर्ष धान की फसल आने के बाद सरकारी संस्थाओं द्वारा किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर राज्य-वार कितना-कितना धान खरीदा गया है;

(ख) क्या यह पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया गया है कि किसान गैर-सरकारी ठेकेदारों को किस-किस दर पर धान बेच रहे हैं;

(ग) किसान किन-किन कारणों से धान की फसल गैर-सरकारी ठेकेदारों को बेचने के लिए बाध्य होते हैं; और

(घ) विगत तीन वर्षों में आज की तारीख तक, किसानों से राज्य-वार कितना-कितना धान खरीदा गया है?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री राम विलास पासवान): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) केंद्रीय सरकार, भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य सरकार/सरकारी एजेंसियों के माध्यम से देश में धान और गेहूं के लिए मूल्यय समर्थन प्रदान करती है। इस नीति के अंतर्गत किसानों द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर लाया गया गेहूं और धान, जो भारत सरकार द्वारा पहले से निर्धारित विनिर्दिष्टियों (अच्छीह औसत गुणवत्ता मानदंड) के अनुरूप होता है, राज्यी सरकार की एजेंसियों और भारतीय खाद्य निगम द्वारा केन्द्रीय पूल के लिए न्यूतनतम समर्थन मूल्य पर खरीद लिया जाता है। तथापि, किसान अपनी उपज को खुले बाजार में बेचने के लिए स्वतंत्र है, यदि उन्हें मूल्य और परिस्थितियां अनुकूल लगती हैं। विगत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान सरकारी एजेंसियों द्वारा केन्द्रीय पूल के लिए न्यूउनतम समर्थन मूल्यत पर किसानों से खरीदे गए धान की मात्रा का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है (नीचे **देखिए**)।

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने किसानों द्वारा निजी कांट्रेक्टरों को की जा रही धान की बिक्री की दर का पता लगाने के लिए कोई अध्यायन नहीं किया है। तथापि, ऐसे अनेक कारण हो सकते हैं, जिनकी वजह से किसान अपने धान की बिक्री निजी कांट्रेक्टरों को करते है। जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ बाजार में बेहतर मूल्य की उपलब्धता, स्टाक के निपटान की तात्कालिक आवश्यकता, भंडारण स्थान का अभाव आदि शामिल हैं।

अनुबंध

धान की राज्य-वार खरीद दर्शाने वाला विवरण

(आंकड़े लाख टन में)

राज्य	खरीफ विपणन मौसम 2015-16	खरीफ विपणन मौसम 2016-17	खरीफ विपणन मौसम 2017-18	खरीफ विपणन मौसम 2018-19*
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	64.72	55.58	59.70	18.47
तेलंगाना	23.57	53.67	54.00	35.19
असम	0.63	0.69	0.53	0.03
बिहार	18.28	18.42	11.84	0.03
चंडीगढ़	0.24	0.19	0.21	0.19
छत्तीसगढ़	51.37	60.03	47.87	40.43
दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00
गुजरात	0.01	0.01	0.01	0.13
हरियाणा	42.70	53.48	59.58	58.35
हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5
झारखंड	3.03	2.07	2.14	0.11
जम्मू और कश्मीर	0.10	0.12	0.19	0.14
कर्णाटक	0.81	0.00	0.00	0.00
केरल	5.62	4.53	4.84	0.85
मध्य प्रदेश	12.67	19.61	16.35	5.73
महाराष्ट्र	3.43	4.61	2.67	2.27
नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00
ओडिशा	50.29	54.18	49.06	13.26
पुडुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00
पंजाब	139.56	164.96	176.61	169.11
राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00
त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.02
तमिलनाडु	17.78	2.11	14.87	2.12
उत्तर प्रदेश	43.44	35.14	42.90	23.41
उत्तराखंड	8.93	10.54	0.57	5.98
पश्चिम बंगाल	23.06	28.28	24.60	0.44
कुल	510.24	568.22	568.54	376.26

*खरीफ विपणन मौसम 2018-19 से संबंधित आंकड़े दिनांक 01.01.2019 की स्थिति के अनुसार

Procurement of paddy

†*250. SHRIMATI CHHAYA VERMA: Will the Minister of CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) the quantum of paddy procured by Government agencies on Minimum Support Price (MSP) from farmers after harvesting of paddy crop this year, State-wise;

(b) whether any study has been conducted to find out the rate at which the farmers are selling paddy to the private contractors;

(c) the reasons due to which the farmers are forced to sell their paddy crop to the private contractors; and

† Original notice of the question was received in Hindi.

(d) the quantum of paddy procured from the farmers in the last three years till date, State-wise?

THE MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI RAMVILAS PASWAN): (a) to (d) A statement is laid on the table of the House.

Statement

(a) to (d) The Central Government extends price support to paddy and wheat through the Food Corporation of India (FCI) and State Government/Government Agencies across the country. Under this policy, wheat and paddy offered by farmers, within the stipulated period and conforming to the specifications (Fair Average Quality norms) prescribed in advance by Government of India, are purchased at Minimum Support Price (MSP) by the State Government agencies and Food Corporation of India (FCI) for Central Pool. However, farmers are free to sell their produce in the open market if they find the price and conditions favourable. State-wise details of the quantum of paddy procured from the farmers by the Government Agencies for Central Pool at Minimum Support Price (MSP) during last three years and current year is given in Annexure (*See* below).

The Department of Food and Public Distribution has not conducted any study to find out the rate at which the farmers are selling paddy to the private contractors. However, there can be various reasons due to which farmers may sell their paddy to the private contractors, which *inter alia* include, availability of better market price, immediate need for disposal of stock, lack of storage space etc.

Annexure

Statement showing State-wise paddy procurement

(Fig. in LMT)

States	KMS			
	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19*
1	2	3	4	5
Andhra Pradesh	64.72	55.58	59.70	18.47
Telangana	23.57	53.67	54.00	35.19
Assam	0.63	0.69	0.53	0.03
Bihar	18.28	18.42	11.84	0.03
Chandigarh	0.24	0.19	0.21	0.19

1	2	3	4	5
Chhattisgarh	51.37	60.03	47.87	40.43
Delhi	0.00	0.00	0.00	0.00
Gujarat	0.01	0.01	0.01	0.13
Haryana	42.70	53.48	59.58	58.35
Himachal Pradesh	0.00	0.00	0.00	0.00
Jharkhand	3.03	2.07	2.14	0.11
Jammu and Kashmir	0.10	0.12	0.19	0.14
Karnataka	0.81	0.00	0.00	0.00
Kerala	5.62	4.53	4.84	0.85
Madhya Pradesh	12.67	19.61	16.35	5.73
Maharashtra	3.43	4.61	2.67	2.27
Nagaland	0.00	0.00	0.00	0.00
Odisha	50.29	54.18	49.06	13.26
Puducherry	0.00	0.00	0.00	0.00
Punjab	139.56	164.96	176.61	169.11
Rajasthan	0.00	0.00	0.00	0.00
Tripura	0.00	0.00	0.00	0.02
Tamil Nadu	17.78	2.11	14.87	2.12
Uttar Pradesh	43.44	35.14	42.90	23.41
Uttrakhand	8.93	10.54	0.57	5.98
West Bengal	23.06	28.28	24.60	0.44
TOTAL	510.24	568.22	568.54	376.26

* KMS 2018-19 figures as on 01.01.2019.

श्रीमती छाया वर्माः सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि धान खरीदी का पंजीयन 31 अक्तूबर को समाप्त हो जाता है। विभिन्न राज्यों में अलग-अलग तारीख होती है। धान बेचने की तारीख तीन महीने बाद दिसंबर में होती है। इन तीन महीनों के बीच में किसी किसान की मृत्यु हो जाती है, तो क्या उस किसान का परिवार धान को सोसायटी में नहीं बेच पाता है? उसे उस धान को कोचिया को बेचना पड़ता है या दूसरी जगह बेचना पड़ता है, तो किसान के उस नुकसान की भरपाई और उसको राहत देने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी.आर. चौधरी): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी ने जानना चाहा कि धान की जो फसल है, वह 31 अक्तूबर या तीन महीने का जो भी समय है, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं कि हमारा जो

खरीफ मार्केटिंग सीज़न है, वह October से next September तक चलता है, क्योंकि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं, जहां पर धान की दो फसल भी होती है, तो right from अक्तूबर से सितंबर तक धान की फसल होती है और एफसीआईएन जहां तक क्योंकि जब यह क्वेश्चन ही है और किसान का अनाज एफसीआई के माध्यम से और स्टेट एजेंसी के मार्फत प्रोक्योर किया जाता है, अनाज जो धान वगैरह है और जहां तक छत्तीसगढ़ का है, अभी तक 40 लाख टन के करीब धान प्रोक्योर हो चुका है और अभी तक जारी है।

श्रीमती छाया वर्माः सर, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि गरीब आदमी रेग लेकर दूसरे आदमी की खेती करता है, किसानी करता है, लेकिन जो बोनस का पैसा होता है, वह खेती करने वाले को नहीं मिलता है। वह बोनस का पैसा जिसकी जमीन होती है, उसके खाते में चला जाता है। मैं पूछना चाहती हूं कि सरकार इसके लिए क्या कदम उठाएगी?

श्री सी. आर. चौधरीः महोदय, हमारा जो सिस्टम है, procurement खातेदार से किया जाता है। जो स्वयं खातेदार है, उसके मार्फत ही procurement होता है। जहां तक sub-tenant का सवाल है, उसका कोई प्रावधान नहीं है लेकिन tenant अपनी जमाबंदी के साथ, कि मेरा इतना अनाज पैदा हुआ है और इसमें से मैं इतना दे रहा हूं, तो उसी को दिया जा रहा है। Sub-tenant के नाम से कोई प्रोविज़न नहीं है, लेकिन अगर दो काश्त के, tenant-2 and tenant-3 tenants हैं, एक ही खाते में चार नाम हैं तो चारों में से proportionately लिया जाता है। दूसरा जो आप बता रही हैं, उस प्रकार का प्रावधान है ही नहीं।

श्री सभापतिः रामविलास जी, यह विषय थोड़ा नाज़ुक है, लेकिन practical है। आगे इसके बारे में आप लोग आपस में स्टडी कीजिए। Sub-tenant गांव में क्या होता है, आपको भी मालूम है।

श्री रामविलास पासवानः सर, हम लोग इस बारे में सोच रहे हैं और इस संबंध में हम लोग आपसे भी मिलेंगे।

श्री सभापतिः ठीक है, धन्यवाद। प्रश्न संख्या 251

Remedial measures to extend help to loss making farmers

*251. SHRI A. VIJAYAKUMAR: Will the Minister of AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government is aware that high yield of vegetables, such as onions, tomatoes, brinjals, etc., caused loss to farmers in the country;

(b) if so, the remedial measures taken to extend help to loss-making farmers; and

(c) whether Government has any proposal to train farmers to make value-added products from the yield, such as onions, tomatoes, brinjals, etc.?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (SHRI RADHA MOHAN SINGH): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.